Peer Reviewed Journal for M.Phil. , Ph.D. & Appointment of Teacher in Universities & College

ISSN : 2454-4655 VOLUME - 8 No. : 4, May - 2022

International Journal of Social Science & Management Studies

Peer Reviewed & Refereed Journal

Indexing & Impact Factor 5.2

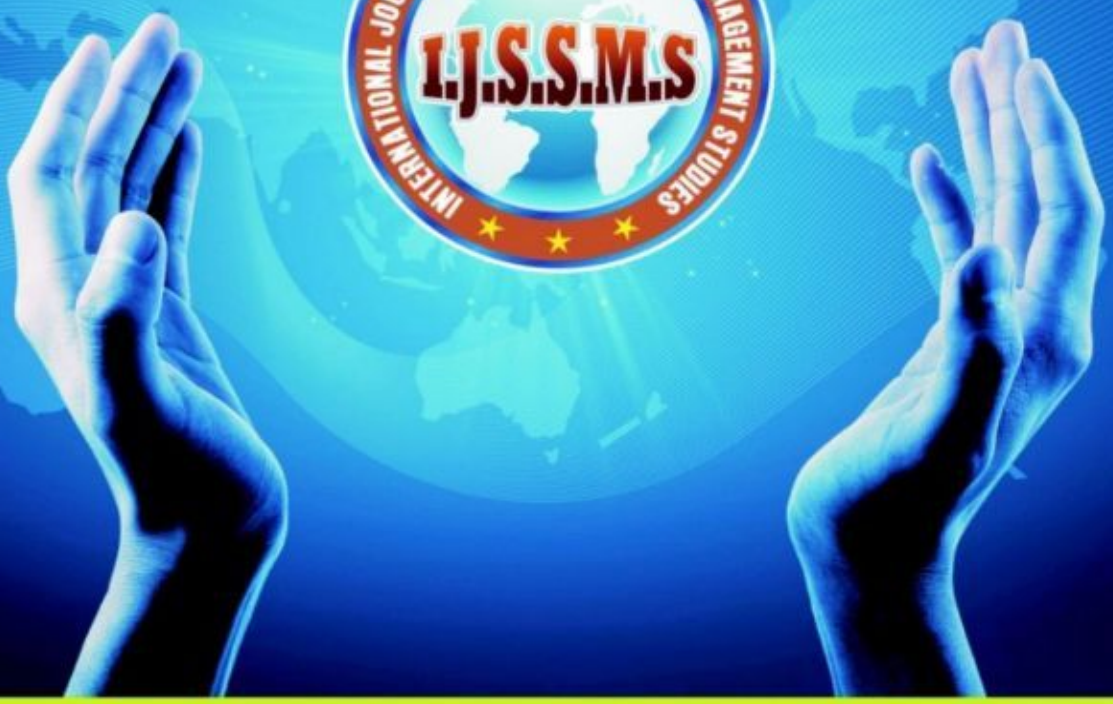

Indian Tech

GLOBAL CERTIFICATION SERVICES

ISRS International Scientific Research Solution

International Journal of Social Science & Management Studies

International Journal of Social Science & Management Studies (I.J.S.S.M.S.)
Peer Reviewed-Refereed Research Journal, Indexing & Impact Factor - 5.2, Ex - UGC S.N. 5351
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 8, No. - 4, May - 2022, Special Issues

2022

भारत की विदेश नीति के 75 वर्ष : एक अवलोकन

डॉ. श्रवण कुमार त्रिपाठी
असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्रभारी, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग, दयानन्द वैदिक कॉलेज, उरई (जालौन), उत्तर प्रदेश

सार :– भारत विश्व की प्राचीनतम और महानतम सभ्यताओं में से एक है तथा मजबूत संस्कृति का वाहक है। स्वाधीनता के पश्चात भारत ने जिस विदेश नीति का अनुसरण किया वह भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं राजनीतिक परम्परा को प्रतिबिम्बित करती है तथा इसके साथ ही भारत की विदेश नीति स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आदर्शों एवं दूरदर्शिता से प्रेरित है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के नीति–निर्माताओं ने अपने प्राचीन आदर्श वैश्विक शान्ति, सुरक्षा तथा मानवता पर चलते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति हेतु स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया है। वैश्विक स्तर पर भारत विभाजन से उत्पन्न संघर्ष की स्थिति, शीतयुद्ध की परिस्थिति, शीतयुद्धोत्तर काल में वैश्विक स्तर पर नवीन विश्व व्यवस्था के उदय, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की शुरुआत, कोरोना काल की स्थिति तथा वर्तमान समय में रूस–यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न वैश्विक परिस्थितियों में भारत ने अपनी विदेश नीति को देश, काल एवं परिस्थिति के अनुरूप राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया है।

प्रत्येक राष्ट्र विश्व के विभिन्न राष्ट्रों से अपने राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक सम्बन्ध बनाने का प्रयास करता है जिससे कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दे सके। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में कोई भी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थ नहीं रह सकता है। अतः प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए अन्य राष्ट्रों से सम्बन्धों में उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिस नीति का अनुसरण करता है उसे विदेश नीति कहा जाता है।[1] किसी देश की विदेश नीति की परिकल्पना, रूपरेखा और निर्माण, विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सम्बन्ध के आधार पर राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है तथा यह किसी देश के परम्परागत मूल्यों, समग्र राष्ट्रीय नीतियों, आकांक्षाओं और स्व–धारणा का प्रत्यक्ष प्रतिविम्ब होती है।[2] अतः जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य विदेश नीति का मूल्यांकन करते है तो पाते हैं कि भारत की विदेश नीति का उद्देश्य सकारात्मक एवं सक्रिय वैश्विक भागीदारी के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उसे बढ़ावा देते हुए विकास की ओर अग्रसर होना है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और समृद्धि है।[3]

भारत विश्व की प्राचीनतम और महानतम सभ्यताओं में से एक है तथा मजबूत संस्कृति का वाहक है।[4] स्वाधीनता के पश्चात भारत ने जिस विदेश नीति का अनुसरण किया वह भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं राजनीतिक परम्परा को प्रतिबिम्बित करती है तथा इसके साथ ही भारत की विदेश नीति स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आदर्शों एवं दूरदर्शिता से प्रेरित है,[5] जिसमें आचार्य कौटिल्य का यथार्थवादी चिन्तन, सम्राट अशोक द्वारा अपनाया गया शांति, स्वतंत्रता एवं समानता, भारतीय परम्परा का मौलिक सिद्धांत 'वसुधैव कुटुम्बकम', स्वामी विवेकानन्द के उच्च आदर्श, महात्मा गांधी का सत्य एवं अहिंसा तथा पण्डित जवाहरलाल नेहरू का गुटनिरपेक्षता का सिद्धान्त परिलक्षित होता है।[6]

स्वतन्त्र भारत के नीति निर्माता विदेश नीति में स्वामी विवेकानन्द के उस आदर्श को लेकर अग्रसित हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि "भविष्य में भारत को विश्व में शान्ति के दूत, न्याय एवं नैतिक आधार पर विश्व व्यवस्था के अग्रदूत की भूमिका निभानी है।"[7] इसके साथ ही महात्मा गाँधी के मंतव्य, एक देश का हित दूसरे देश के हित से इस प्रकार समायोजित होना चाहिए जिससे मानवता के हित को बढ़ावा मिल सके, को विशेष महत्व के साथ विदेश नीति में समाहित किया गया। अतः भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति में वैश्विक हितों को समाहित करते हुए विश्व शान्ति को महत्व दिया। उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि " हमारा यह प्रयत्न होगा कि भारत के राष्ट्रीय हितों की समीक्षा और सुरक्षा विश्व शांति और अन्य देशों से सहयोग के परिप्रेक्ष्य में की जाए, तथा भारत उस सीमा तक जाने को प्रस्तुत होगा जहाँ तक ऐसा करना विश्व शांति को सुनिश्चित कर सके।"[8] इसलिए भारत द्वारा विदेश नीति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने संविधान के अनुच्छेद 51 में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के मध्य न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने तथा विवादों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।[9]